2019 में अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी

तरुण दास

साल 2019 चुनावी साल है, ऐसे में चुनाव के बाद बनने वाली किसी भी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी। सवाल है इसके साथ नई सरकार किस तरह डील करेगी? इस संदर्भ में पहली बात तो हमें यह समझनी होगी कि इस समय जो सरकार है, अस्तित्व में है, वह आज की तारीख में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। हाल ही में मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में जो कटौती की है, वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास इस बात में दिखता है कि उसने बैंकों को सुचारू रूप से अपना कामकाज करने के लिए अतिरिक्त पूंजी मुहैय्या कराई है।

बैंकों को अतिरिक्त पूंजी इसलिए प्रदान की गई है, जिससे कि वे उद्योगों को ज्यादा कर्ज दे सकें। इस पहल से मुझे उम्मीद है कि साल 2019 की पहली तिमाही में विकास दर बढ़ेगी। मेरा यह भी अनुमान है कि 1 फरवरी 2019 को पेश किए जाने वाले बजट में कुछ बेहतर घोषणाएं की जाएंगी ताकि अर्थव्यवस्था को उठान मिले। बजट के बाद के तीन महीने की अवधि चुनाव और नई सरकार के गठन में लग जाएंगे। ऐसे में कोई नई पहल जून 2019 के बाद ही देखने को मिलेगी। मेरा मानना है की जीएसटी दरों में की गई कमी से आने वाले दिनों में इन वस्तुओं की मांग में तेजी से बढ़ोतरी होगी। चूंकि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पूंजी है, इसलिए आने वाले दिनों

2019 में ऐसे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो ग्रामीण व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं। क्योंकि इन्हीं से अतिरिक्त रोजगार मिलने की संभावना है। ध्यान रखिए जो बड़े उद्योग हैं, वे पूंजी प्रधान है, इसलिए वे ऑटोमोटिव तकनीकों पर जोर देते है, उनसे हमें रोजगार मिलने की कम ही उम्मीद है।

में कर्ज दिए जाने की गति में भी बढ़ोतरी होगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को गति मिलेगी।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय सरकार की सबसे बड़ी चिंता कृषि क्षेत्र को लेकर दिख रही है। किसानों की दुर्दशा कितनी सुधरेगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें यह भी मानकर चलना होगा कि इस क्षेत्र में हो रहे तमाम प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि यह साल यानी 2019 आर्थिक विकास की दर से बेहतर साल होगा। मेरे इस आशावाद की वजह ये है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इस समय जो कोशिशें हो रही हैं, उनके नतीजे हमें साल 2019 में मिलेंगे। साल 2019 में मेक इन इंडिया अभियान को भी नए सिरे से गति मिल सकती है। इसके लिए हमें भारत के सभी मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगों को वैश्विक सप्लाई चेन से जोड़ना होगा। इसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि किस क्षेत्र में निर्यात की बेहतर संभावनाएं हैं और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है।

अगले साल कृषि के मोर्चे पर जबरदस्त उथल-पुथल की संभावनाएं हैं; क्योंकि कृषि भारत की एक दीर्घकालीन

चुनौती है। यदि हम अपने कृषि क्षेत्र को अलग-अलग करें तो हमारे यहां करोड़ों छोटे किसान हैं, अनेक किस्म के कृषि उत्पाद हैं, इन सबसे राज्य सरकारें गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनसे त्वरित परिणाम पाना संभव नहीं है। हमें कृषि नीति को दीर्घकाल को ध्यान में रखकर और दीर्घकाल के फायदे को ध्यान में रखकर निरूपित करने की जरूरत है। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि इनका क्रियान्यवन एक भारी चुनौती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी सरकार में भी निर्यात के मोर्चे पर प्रदर्शन आशाजनक नहीं रहा। रुपये के गिरते मूल्य ने भी इसे संकटपूर्ण बनाया है। ऐसे में यह सवाल पूछा जाना स्वभाविक है कि क्या साल 2019 में इस स्थिति में सुधार की संभावना है?

मैं कहूंगा हां, सुधार की संभावना है बशर्ते हम इसके लिए अपना मुख्य ध्यान टैक्सटाइल और मशीन उपकरणों पर केंद्रित करें। इसके बाद हमें अपनी कार्ययोजना उन उत्पाद समूहों पर फोकस करना चाहिए जो इस टैक्सटाइल और उपकरण के मातहत आते हों। इसके साथ ही हमें अपने व्यापार को दुनिया के अलग-अलग भौगोलिक केंद्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए, जिससे हम अपना व्यापार बढ़ा सकें। अमेरिका और चीन दुनिया के दो बड़े व्यापारी देश हैं, जिनको देखते हुए हमें अपना विशेष निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस प्रयास से देश में रोजगार का स्तर भी बढ़ सकता है, लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि यह सब तभी संभव है जब देश के उद्यमियों को छोटे-छोटे कर्ज और उन्हें यथोचित मार्ग निर्देश दिए जाएं।

हमें खासकर ऐसे नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो ग्रामीण व्यवसाय के विशेषज्ञ हैं। क्योंकि इन्हीं से अतिरिक्त रोजगार मिलने की संभावना है। ध्यान रखिए जो बड़े उद्योग हैं, वे पूंजी प्रधान है, इसलिए वे ऑटोमोटिव तकनीकों पर जोर देते है, उनसे हमें रोजगार मिलने की कम ही उम्मीद है।

(लेखक देश के जाने माने अर्थशास्त्री तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के पूर्व चीफ मेंटर हैं। यह लेख इकोनॉमी इंडिया के संपादक मनोहर मनोज की उनसे हुई बातचीत पर आधारित है)